भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3320

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में बाढ़ का प्रभाव

3320. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में बाढ़ के प्रभाव विशेषकर पिछले पांच वर्षों के दौरान मानव जीवन, कृषि, आवास और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की सीमा के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, विशेष रूप से एलुरु जिले में बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए गए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एलुरु में बाढ़ क्षति शमन और न्यूनीकरण के विकास के लिए विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर एलुरु जिले और आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): अपेक्षित सर्वेक्षण के आयोजन सहित, बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों में सहयोग करती है। केंद्र सरकार, वर्ष 2021-26 के दौरान बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी उपाय, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी उपाय आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" कार्यान्वित कर रही है।

आंध्र प्रदेश की ओर से एफएमबीएपी के अंतर्गत शामिल करने हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि थम्मिलरू, येर्राकलवा और कोव्वाडा कालवा सरप्लस जलमार्गों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को स्वीकृत किया गया और राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) से 470.71 लाख रुपये की से कार्य-निष्पादन किया गया है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत, केंद्रीय जल आयोग आंध्र प्रदेश में 36 जल विज्ञान अवलोकन केंद्र संचालित कर रहा है, जिनमें से दो एलुरु जिले में हैं। केंद्रीय जल आयोग आंध्र प्रदेश में 21 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र भी संचालित करता है, जिनमें से एक एलुरु जिले में है। बाढ़ संबंधी चेतावनियों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय जल आयोग विभिन्न प्रसार तंत्रों का उपयोग करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जल संसाधन विभाग के साथ-साथ राजस्व और वन विभाग ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बाढ़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के संबंध में जनता में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न पहले शुरू की हैं।

*****